प्रधान मंत्री द्वारा नेशनल 2006 पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट जारी करना

जनवरी 12, 2007
नई दिल्ली

मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (नेशनल नॉलेज कमीशन)द्वारा परिकल्पित दो पोर्टल्स शुरू कर रहे हैं। हमने यह आयोग इसलिए गठित किया क्योंकि हमारा मानना है कि भारत में हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी जनता की क्षमताओं को विकसित करना है। लंबे समय से हम अपने देश की आबादी को आर्थिक एवं सामाजिक दायित्व के रूप में देखते आए हैं। लेकिन शिक्षित, दक्ष,स्वस्थ सशक्त लोगों का देश की उन्नति में बहुत योगदान होता है। हमारे समक्ष प्रत्येक नागरिक का भारत के विकास में योगदान सुनिश्चित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है।

हमें इस चुनौती का निराकरण करने के लिए वित्तीय निवेश तथा सृजनात्मक चिंतन दोनों की आवश्यकता है। जैसा कि मैने इस आयोग के गठित होने के समय कहा था कि हमें ज्ञान पिरामिड के प्रत्येक स्तर पर अपनी जनता की क्षमताओं में निवेश करना होगा। अपने सामाजिक एवं ज्ञान पिरामिड के आधार को सशक्त करना होगा तथा उसके शीर्ष को क्रियाशील करना होगा। यद्यपि सरकार को वित्तीय संस्थानों का पता लगाना होगा लेकिन सृजनात्मक चिंतन प्रत्येक पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए कि मैने 'ज्ञान आयोग' का गठन किया है।

लोक स्तर पर यदि विचार किया जाए तो वास्तविक चुनौती लोगों के विचारों को बदलना तथा ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के सृजनात्मक साधनों का पता लगाना है। मुझे यह जानकर खुशी है कि आपने " पिरामिड के सबसे निचले हिस्से " की सबसे बड़ी समस्या यानि अभिगम्यता को संबोधित किया है। आपकी दस मे से छः सिफारिशें सीधे अभिगम्यता से संबधित हैं। यह समन्वित समाज निर्माण के उद्देश्य के अनुकूल है जो हमारी सरकार का निर्देशक सिद्धांत है।

मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि आपने सार्वजनिक पुस्तकालयों मे सुधार के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यह हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग की ज्ञान संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। आपने ज्ञान के प्रसार को सुलभ बनाने के लिए व्यावहारिक अनुवाद पद्धति के महत्व को भी उजागर किया है। इसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

आपने सभी विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को सम्बद्ध करने वाला 'नॉलेज नेटवर्क ' प्रस्तावित किया है। इसमें भी अनुवाद को शामिल किया जाना चाहिए। सभी राष्ट्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय पोर्टल्स तैयार करने का विचार प्रशंयनीय है। यह ज्ञान के भंडार विकसित करने में मददगार हो सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग बढ़ने से इनकी उपयोगिता में भी बृद्धि होगी।

हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आयोग की रिपोर्टग में उच्चतर शिक्षा सुधार से संबधित कई उपयोगी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इन सभी विचारों पर गंभीर

विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। मेरा आयोग से आग्रह है कि वह इन विचारों को पूरे देश के समक्ष रखे तथा आम राय ले। व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें पर अर्थव्यवस्था की रोजगार संभावनाओं के विस्तार के संबध में उनके महत्व को देखते हुए तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे आज आयोग के सहयोग से तैयार 'अरघयम ' तथा टी ई आर आई' द्वारा विकसित भारतीय जल पोर्टल तथा भारतीय ऊर्जा पोर्टल की शुरूआत करने में बहुत खुशी हो रही है। ये पोर्टल जटिल एवं बहुनिवेशधारियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को काम में लाने का एक अच्छा उदाहरण है। जल प्रयोग विज्ञान खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। सफाई व्यवस्था के अभाव में लोक स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता है। हमारे देश में जल की पर्याप्त मात्रा है। अतः समस्या जल के अभाव की नहीं बल्कि उसके प्रबंधन की है। हमें जल -प्रबंधन में सुधार करना होगा क्योंकि जल संबधी समस्याओं को निवारण इसी में निहित हैं।

भारत में इन क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे है। लेकिन इन विस्तृत क्रियाकलापों को समन्वित करने और उनके प्रसार का अभाव है। इसके लिए लगातार सूचना एवं संसाधनों का आदान-प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे -जल ऊर्जा,पर्यावरण,शिक्षा तथा नागरिक अधिकारों के सबध में राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल तैयार करने में सहयोग प्रदान करने में पहल की है। यह अपनी जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए जानकारी का प्रयोग करने का एक अच्छा उदाहरण है।

इन पोर्टल्स के फायदे जनता तक पहुॅच रहे हैं इस के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों तथा इनसे हमारे नागरिकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं का निवारण होता हो।

हम आशा करते हैं कि आगामी वर्ष में आयोग,विशेषकर हमारे विद्यालयों में सुधार किए जाने, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने, कृषि तथा छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमों की जानकारी प्रदान करने संबधी आवश्यकताओं को पूरा करने और नवोत्पाद व उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाने के क्षेत्र में और अधिक कार्य करेगा।

मैं पुनः यह कहना चाहूॅगा कि आयोग की भूमिका सरकारी नीति में सुधार निर्देशित करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। बल्कि आयोग को अपने नवीन विचारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कार्य में भी जुटाना चाहिए। अंततः इसे समाज के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करना होगा जो सूचना सदी (नॉलेज सेंचुरी)में मार्ग प्रशस्त कर सके।

****